रिट याचिका) जो भूमि के कुछ आदान-प्रदान की भी बात करती है और वर्षों के लिए जामबंदियों 1983-84 और 1988-89 से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के पास विनिमय के कारण भूमि का कब्जा है।यह सच है कि याचिकाकर्ताओं को जामबंदियों में मालिकों के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन *प्रथमदृष्टया उन्होंने* स्वामित्व का सवाल उठाया है और मेरी राय में, सहायक कलेक्टर अधिनियम की खंड 13-ए के तहत इस तरह की याचिका का निपटारा नहीं करना उचित नहीं था। उस स्तर पर, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को केवल प्रथमदृष्टया संतुष्ट किया जाना है और *अधिनियम की* खंड 13-ए के तहत खुद को न्यायाधिकरण में परिवर्तित करने के बाद ही पक्ष अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।यदि याचिकाकर्ता अपना हक साबित करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अनधिकृत अधिभोगियों के रूप में विवादित भूमि से बाहर निकाल दिया जाएगा।दूसरी ओर, यदि वे अपना स्वामित्व स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी दावा किया है, तो ग्राम

पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज करना होगा।मेरी राय में, वर्तमान मामले में न केवल अधिकार का सवाल उठाया गया था, बल्कि प्रथमदृष्टया भी साबित हुआ था *ताकि अधिनियम* की खंड 13-ए के तहत निर्णय की आवश्यकता हो। मामले के इस दृष्टिकोण में, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी और अपील में कलेक्टर द्वारा पारित किए गए विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।इस मामले को एक निर्देश के साथ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र को भेज दिया गया है।अधिनियम की खंड 13-ए के प्रावधानों के संदर्भ में स्वामित्व के प्रश्न का पहले निपटारा करना। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें जो कुछ भी कहा गया है वह मामले के गुण-दोष के प्रति मेरे विचारों की अभिव्यक्ति नहीं है और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को उन साक्ष्यों के आधार पर इस मुद्दे का फैसला करना होगा जो पक्षकारों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।नतीजतन, रिट याचिका को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।पक्षकारों को अपने वकील द्वारा से आगे की

कार्यवाही के लिए 18 नवंबर, 1991 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी कुरुक्षेत्र के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

जे एस टी _

माननीय ए. एल. बहरी *और एन. के. कपूर, न्यायाधीश*

बाबू राम अग्रवाल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा सरकार और अन्य लोगों के लिए आयोग और सचिव-

उत्तरदाता।

1993 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 15057

6जनवरी, 1994

भारत का संविधान 1950-कला।226/227–हरियाणा *नगरपालिका* अधिनियम धारा 21 और 27-अविश्वास *प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई*

केवल 2 सदस्यों ने भाग लिया-बैठक कोरम की कमी के आधार *पर स्थगित कर दी गई-कार्रवाई स्थगन बैठक को चुनौती* दी गई-चूंकि *खंड* 21 *की उप-खंड (1) के तहत* बनाए गए *कोई नियम नहीं हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव* के *मामले* में कोरम *के संबंध में प्रावधान आकर्षित नहीं किए गए-अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक को नगर समिति के सामान्य कार्य के दायरे में नहीं कहा जा सकता है-आदेश स्थगन बैठक को दरकिनार कर दिया गया।*

अभिनिर्धारित किया गया कि यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि नगरपालिका समिति के सभी 21 सदस्यों को 1 दिसंबर, 1993 को आयोजित होने वाली बैठक में विधिवत सेवा प्रदान की गई थी।कड़ाई से कहें तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक एक साधारण बैठक या विशेष बैठक के दायरे में नहीं आती है क्योंकि मामला नगर समिति के कार्य के लेन-देन से संबंधित नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव को नगर समिति का एक सामान्य कार्य नहीं माना जा सकता है।चूंकि

खंड 21 की उप-खंड (1) के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव की *बैठक* के मामले में गणपूर्ति के संबंध में प्रावधान आकर्षित नहीं किया जाता है।

(पैरा 6)

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम-धारा 21-अविश्वास *प्रस्ताव-सभी* सदस्यों *को उचित सूचना दी गई-21 में से केवल दो ने भाग* लिया-स्वाभाविक निष्कर्ष *कि प्रस्ताव खारिज हो गया।*

आयोजित किया गया कि सभी 21 सदस्यों को इच्छित बैठक के बारे में सूचित किया गया था जो दोनों को छोड़कर किसी भी तरह से उपस्थित नहीं हुए थे।स्वाभाविक निष्कर्ष यह होगा कि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था।

(पैरा 6)

याचिकाकर्ता की ओर से *एस. के. मित्तल, अधिवक्ता*

अरुण नेहरा, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा, *प्रतिवादी के लिए।*

निर्णय

एन. के. कपूर न्यायाधीश

याचिकाकर्ता ने 1 दिसंबर, 1993 के आक्षेपित नोटिस, संलग्नक पी-2 को रद्द करने के लिए सरशियोरेराई जारी करने की मांग की *है,* जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 ने इस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक को स्थगित *कर दिया कि इसमें आवश्यक कोरम की कमी है।*

अदालत द्वारा हरियाणा के अधिवक्ता को जारी प्रस्ताव के नोटिस के अनुसरण में, प्रतिवादी ने उपस्थित होकर लिखित बयान दायर किया और रिट याचिका की स्थिरता के साथ-साथ याचिका की योग्यता को चुनौती दी।चूंकि मामला जरूरी था, इसलिए प्रस्ताव की सुनवाई में इसे अंतिम निर्णय के लिए लिया गया।

याचिकाकर्ता को नगर समिति, नारनौल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और याचिका में किए गए अभिकथनों के अनुसार वह नगर समिति के अध्यक्ष के रूप में ईमानदारी और ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।नगरपालिका समिति में 19 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्यों को नामित किया गया है।' इस प्रकार नगर समिति, XNarnaul के सदस्यों की कुल संख्या 21 है, याचिकाकर्ता के विपरीत समूह से संबंधित सदस्यों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए एक बैठक बुलाने के लिए उपायुक्त, नारनौल को एक अनुरोध प्रस्तुत किया।उपायुक्त द्वारा ऐसी बैठक बुलाए जाने से पहले, याचिकाकर्ता का विरोध करने वाले सदस्यों ने 1993 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या *12640* "मुकुट बिहारी संघी बनाम *हरियाणा* राज्य" को चुनने का फैसला किया, जिसमें नगर समिति की बैठक बुलाने के लिए उपायुक्त को परमादेश देने की मांग की गई।याचिका की सुनवाई पूर्वाहन दौरान एस. डी. ओ. (ग) उपायुक्त, नामौल पूर्वाहन आदेश पूर्वाहन अनुसार

नारनौल ने 22 नवंबर, 1993 को हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 197 की खंड 21 (2) पूर्वाहन तहत 1 दिसंबर, 1993 को सुबह 1 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने पूर्वाहन लिए नगर समिति की बैठक बुलाने पूर्वाहन लिए एक नोटिस जारी किया। चूंकि बैठक बुलाई गई थी, इसलिए रिट याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज कर दिया गया था।एस. डी. ओ. द्वारा जारी किए गए नोटिस को देखते हुए। (ग) प्रतिवादी संख्या 3, दो सदस्य 1 दिसंबर, 1993 को सुबह 1 बजे नगर समिति, नारनौल पूर्वाहन कार्यालय में उपस्थित हुए।समिति के अध्यक्ष अर्थात एस. डी. ओ. (ग) प्रतिवादी संख्या 3 ने कोरम पूरा *न* होने के आधार पर बैठक को 10 दिसंबर, 1993 के लिए स्थगित कर दिया।इसी आदेश को इस रिट याचिका में चुनौती दी जा रही है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्राथमिक निवेदन यह है कि एस. डी. ओ. का आदेश। (ग) बैठक को 10 दिसंबर, 1993 तक स्थगित करना कानून के खिलाफ है।हरियाणा नगरपालिका अधिनियम

की खंड 21 का उल्लेख करते हुए, वकील ने आग्रह किया कि अधिनियम की खंड 21 में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसमें अविश्वास बैठक को स्थगित करने की परिकल्पना की गई हो।चूंकि अधिनियम की खंड 21 (1) के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इस मामले का अर्थ खंड 21 के आलोक में लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह मौजूद है।यह तथ्य कि केवल दो व्यक्ति उपस्थित हुए, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को नगर समिति के अधिकांश सदस्यों का विश्वास था।किसी भी मामले में, कोरम की कमी के कारण ऐसी बैठक को स्थगित करने के लिए अधिनियम के तहत कोई *प्रावधान* नहीं होने के कारण, आदेश संलग्नक पी-2 कानून में टिकाऊ नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा बैठक को 10 दिसंबर, 1993 तक स्थगित करते हुए शुरू की गई कार्रवाई में आग्रह किया गया कि चूंकि बैठक में विचार के लिए बुलाया गया था, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव अधिनियम की खंड 27 (1) की अनिवार्य *आवश्यकता* को पूरा नहीं करता है, जिसमें ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति की परिकल्पना

की गई है।द.

बैठक को स्थगित करने का आदेश उन परिस्थितियों में पूर्ण रूप से उचित और उचित था, किसी भी मामले में, यदि कोई याचिकाकर्ता के इस दावे पर चलता है कि उसके पास उसका समर्थन करने के लिए आवश्यक बहुमत है, तो इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्थगन या कोई कानूनी शिकायत नहीं की जा सकती है।विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम में दो प्रकार की बैठकों की परिकल्पना *की* गई है अर्थात (i) सामान्य; और (ii) विशेष।इन दोनों बैठकों में कोरम निर्धारित किया गया है।अधिनियम की खंड 21 के प्रावधानों को अधिनियम की खंड 27 में निहित प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह से, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से न्यायसंगत और कानूनी है।

हमने अभिलेख पर सामग्री के आलोक में संबंधित वकील की दलीलों

पर विचार किया है।तथ्य वास्तव में विवाद में नहीं हैं।नगरपालिका समिति के अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता का विरोध करने वाले सदस्यों ने उन पर कोई विश्वास नहीं व्यक्त किया और एस. बी. ने इस अदालत से उपायुक्त, नारनौल के खिलाफ ऐसी बैठक बुलाने का निर्देश देने की मांग की।न्यायालय द्वारा वांछित राहत दिए जाने के बाद भी मामले को आगे बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना गया जैसा कि संलग्नक पी-2 में देखा गया है जब नगरपालिका समिति के 21 सदस्यों में से केवल दो सदस्य ऐसी बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में उपस्थित हुए थे।यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि नगरपालिका समिति के सभी 21 सदस्यों को 1 दिसंबर, 1993 को होने वाली बैठक के लिए विधिवत सेवा प्रदान की गई थी।कड़ाई से कहें तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक एक साधारण बैठक या विशेष बैठक के दायरे में नहीं आती है क्योंकि मामला नगर समिति के कामकाज के लेन-देन से संबंधित नहीं है।अविश्वास प्रस्ताव को नगर

समिति का एक सामान्य कार्य नहीं माना जा सकता है।चूँकि खंड 21 की उप-खंड (1) के तहत कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव *की* बैठक के मामले में क्वॉर्म के संबंध में प्रावधान आकर्षित नहीं होता है।इस न्यायालय को सुरजित मेहता *और अन्य बनाम हरियाणा* राज्य *और अन्य (1) के मामले में* अधिनियम की खंड 21 और 25 के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था। अधिनियम की खंड 21,25 और हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 के नियम 70 में निहित प्रावधानों की पूरी तरह से जांच करने के बाद, राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव समिति के दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जा सकता है, कुछ प्रक्रियात्मक प्रावधानों का मामूली उल्लंघन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अमान्य नहीं करेगा क्योंकि जिस व्यक्ति को वोट आउट किया गया है, वह तब भी बहुमत का दावा कर सकता है जब उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को चुनने के लिए ऐसी बैठक बुलाई जाती है।उस मामले में, न्यायालय कुछ याचिकाकर्ताओं की गैर-सेवा के प्रभाव पर

विचार कर रहा था, जिन्होंने इस प्रकार प्रचार के लिए समय की अपर्याप्तता की शिकायत की थी।में

(1) 1992 (2) पीएलआर 143,

वर्तमान मामले में, सभी 21 सदस्यों को इच्छित बैठक के बारे में सूचित किया गया था, जो दोनों को छोड़कर उपस्थित नहीं हुए थे।स्वाभाविक निष्कर्ष यह होगा कि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था।

हम प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक को कथित कोरम की कमी के *कारण* स्थगित किया जा सकता है क्योंकि हमारा निश्चित विचार है *कि* अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ऐसी कोई कोरम की परिकल्पना नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और आदेश संलग्नक पी-2 को रद्द कर देते हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

जे एस टी।

इससे पहले माननीय वी. के. बाली, जे.

गुरचरण सिंह-आवेदक *याचिकाकर्ता,*

बनाम

मेसर्स राघबीर साइकिल पी. प्राइवेट लिमिटेड ई. टी. सी.,-उत्तरदाता।

1993 का कंपनी आवेदन *संख्या* 46।

में

1987 की कंपनी याचिका संख्या 134

19अप्रैल, 1994।

कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959-नियम 9 *सी. पी.* सी. आदेश 23, *नियम* 3, *खंड 151-मध्यस्थता* अधिनियम-खंड 8,20 और 21-कंपनी *याचिकाएं लंबित-मध्यस्थ की नियुक्ति के* लिए *नियम 9* के तहत आवेदन-दोनों *पक्षों द्वारा दायर ऐसा आवेदन-मध्यस्थ की* नियुक्ति *का आदेश-प्रदान किया गया पुरस्कार-मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने वाले पुरस्कार पर आपत्तियां।*

अभिनिर्धारित किया कि सभी इच्छुक पक्ष इस बात पर सहमत थे

कि उनके बीच अंतर का मामला मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था।आवेदन लिखित रूप में किए गए थे।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी की याचिकाओं के लिए सभी इच्छुक पक्षों के आवेदनों पर पारित आदेश, ऊपर निर्दिष्ट, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को बाधित नहीं कर रहा था या यह कि पुरस्कार भी मध्यस्थता अधिनियम में निहित नियमों के बाहर था।

(पैरा 41)

इसके अलावा, लेखन में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कहने और किसी भी तरह की आपत्ति उठाए बिना मध्यस्थ के समक्ष भाग लेने से, विरोध करने वालों को यह तर्क देने की अनुमति नहीं मिलेगी कि मध्यस्थ और मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया है।स्वयं पुरस्कार) मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं थे। विरोध करने वालों का आचरण स्वीकृति के बराबर है।

(पैरा 42)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा